दिया जाता है अथवा दिए जाने का विचार है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत जैसे गरीब देश में टेलीफोन सुविधा एक आम आदमी की पहुंच के भीतर है, यदि हां, तो किस प्रकार से, यदि नहीं तो टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार का प्रसार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त समाज के अन्य किन-किन वर्गों को टेलीफोन सुविधा से लाभ हुआ है और समाज के किस वर्ग द्वारा इस सुविधा की मांग की गई है, और क्या देश का किसान टेलीफोन की आवश्यकता वाले वर्ग में आता है ।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई :—

(1) यदि स्थानीय टेलीफोन सेवाएं विभागीय कारणों से 14 दिन या उससे अधिक समय तक लगातार बंद/खराब रहती है तो पूर्ण माह के किराए में छूट ।

(2) अखिल भारतीय आधार पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति ।

(3) स्वाधीनता सेनानियों को गैर-ओ० वाई० टी० एस० डब्ल्यू० एस० श्रेणी में एक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए विशेष प्राथमिकता देना ।

(4) 24 घण्टे के भीतर दोष निपटान ।

(5) ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं देना ।

(6) ग्रुप डायलिंग की शुरुआत ।

(7) मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रावधान ।

(8) उन सभी को व्यवहार्य होने पर स्थानीय एस०टी०डी०/ओ०एस० डी० पी० फोन प्रदान करने की नीति उदार बनाना जो इन सेवाओं का संचालन करने के इच्छुक हों ।

(9) तालुक मुख्यालयों को एस०टी०डी० प्रदान करना ।

(ख) यदि टेलीफोन सेवाएं विभागीय कारणों से 14 दिन या उससे अधिक समय तक लगातार बन्द/खराब रहती हैं तो पूरे महीने के किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है । यदि टेलीफोन सेवा 7 दिन या उससे अधिक लेकिन 14 दिन से कम समय तक लगातार खराब रहती है तो प्रोराटा छूट दी जाती है । गलत रीडिंग/गलत बिलिंग की स्थिति में सही/संशोधित बिल जारी करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है ।

(ग) देश के आम आदमी तक टेलीफोन सुविधा तुरन्त पहुंचाने की दृष्टि से स्थानीय एस० टी० डी०/आई० एस० डी० सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति को उदार बना दिया गया है । इन सेवाओं के लिए आवेदनपत्र मंगाने के उद्देश्य से विज्ञापन दिए जाते हैं और इन्हें व्यवहार्यता की शर्त पर उन सभी को प्रदान किया जाता है जो इनके संचालन करने के इच्छुक होते हैं ।

(घ) इन सुविधाओं को प्रदान करने के समान के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । इन सुविधाओं की मांग करने वाले सभी आवेदक किसानों सहित उपयुक्त श्रेणी में इनके लिए आवेदन कर सकते हैं । किसानों के लिए अलग से कोई श्रेणी नहीं रखी गई है ।

Investment by U.S.A. in Telecom Sector

1200. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is fact that Motorola Inc., U.S.A. had offered to invest an amount up-

to $ 100 million in India for any product in telecom sector;

(b) whether it is also a fact that Motorola has withdrawn this offer as no decision was taken for a considerable period;

(c) if so, when the offer was made and when it was withdrawn;

(d) whether it is also a fact that the Chairman of Motorola wrote to the Government of India indicating the withdrawal of their offer and stating that they are investing this amount in China; and

(e) if so, what are the details in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : The question has already been answered by Ministry of Industry on 26-11-92 vide Q. No. 638. Reply is reproduced below :

(a) Motorola Inc. USA had represented a perspective plan for an investment of over 100 million dollars in diverse sectors over a period of time. More specifically they have made 2 proposals with foreign equity amounting to US $ 4.8 million which has since been approved.

(b) to (d) There is no reference in the letter from Chairman, Motorola to Prime Minister regarding the withdrawal of this offer in favour of China.

(e) Does not arise.

संचार मंत्रालय के खर्च में कमी करने के लिए उपाय

1201. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खर्च में कमी करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन उपायों के कार्यान्वयन से कितनी धनराशि की बचत हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) खर्च में कमी करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) पद्धतियों का सरलीकरण करके प्रचालन लागतों में कटौती करना,

(ii) नई प्रौद्योगिकी लागू करना,

(iii) समयोपरि भत्ते, यात्रा व्यय और पैट्रोल के उपभोग जैसे मामलों में सरकार द्वारा जारी किए गए वित्तीय अनुदेशों को सख्ती से लागू करना ।

दूरसंचार विभाग में, जहां सेवाओं में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, बढ़े हुए कार्य-भार का संचालन, कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि करके किया जाता है ।

(ख) बचत की सही राशि बता पाना कठिन है । लेकिन डाक विभाग में 1991-92 के दौरान 1525.10 करोड़ रु० के बजट अनुमान की तुलना में 1506.75 करोड़ रु० का राजस्व व्यय हुआ । इसी प्रकार, दूरसंचार विभाग में 2490.00 करोड़ रु० के बजट अनुमान की तुलना में 2424.38 करोड़ रु० का राजस्व व्यय हुआ ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

1202. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में गत छः वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) सितम्बर, 1992 में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और इन छः वर्षों के दौरान कितने पदों का सृजन किया गया है; और